PK टाइम्स

दैनिक जनता की आवाज...

लोक टुडे

विश्वसनीय खबरों का सर्वश्रेष्ठ अखबार

pktimesnews.com
loktodaynews.com
PK Times News
thepktimesofficial
pk_timesofficial

वर्ष: 12 | अंक: 343 | मूल्य: 1.00 रुपए | पृष्ठ: 4 | रविवार 28 जून 2026 | RNI No. RAJHIN/2013/50649

पंचायत-निकाय चुनाव पर फिर मंडराया संकट

हाईकोर्ट की 31 जुलाई डेडलाइन टूटना तय, सितंबर-अक्टूबर तक खिसक सकता है शेड्यूल

ट्रिपल टेस्ट की चुनौती: ओबीसी आबादी के सटीक आंकड़ों के बिना आरक्षण तय करना नामुमकिन

लोक टुडे। जयपुर

राजस्थान में लंबे समय से अटके पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर जारी असमंजस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा चुनावी प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए तय की गई 31 जुलाई 2026 की सख्त डेडलाइन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर आरक्षण और डेटा जुटाने की धीमी रफ्तार के बीच अब मानसून ने भी दस्तक दे दी है, जिसके चलते यह चुनाव जुलाई के बजाय सितंबर या अक्टूबर 2026 तक खिसकने के पुख्ता संकेत मिल रहे हैं।

डेटा के अभाव में अटकी प्रक्रिया

राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराने के लिए अपनी तरफ से वोटर लिस्ट और मतदान केंद्रों की तैयारी पूरी कर चुका है, लेकिन असली पेंच सरकार के स्तर पर फंसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के 'ट्रिपल टेस्ट' दिशा-निर्देशों के तहत जब तक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग पिछड़े वर्ग की आबादी का सटीक डेटा

नहीं सौंपता, तब तक सीटों पर राजनीतिक आरक्षण का फॉर्मूला तय नहीं किया जा सकता। राज्य चुनाव आयोग ने पंचायती राज और स्वायत्त शासन विभाग को 15 जून को फिर से रिमाइंडर भेजकर डेटा मांगा था, लेकिन विभागों की ओर से अभी तक अंतिम प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए जा सके हैं।

सरकार का बड़ा दांव : चुनाव से ठीक पहले 76 नई नगरपालिकाओं को मंजूरी

इस खींचतान के बीच भजनलाल सरकार ने चुनावों से ठीक पहले एक बड़ा प्रशासनिक दांव खेला है। राज्य सरकार ने प्रदेश में 76 नई नगरपालिकाओं के गठन को हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही शहरी विकास और बेहतर प्रशासन के लिए 684 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है। सरकार के इस फैसले को ग्रामीण क्षेत्रों को अर्द्ध-शहरी निकायों में तब्दील कर अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।

कोर्ट में अतिरिक्त समय मांग सकती है सरकार

सूत्रों के मुताबिक, ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट और वार्डों के नए सिरे से परिसीमन में हो रही देरी को आधार बनाकर राज्य सरकार हाईकोर्ट में अंतरिम प्रार्थना पत्र दाखिल कर सकती है, ताकि चुनाव कार्यक्रम के लिए कुछ और महीनों का अतिरिक्त समय मिल सके। दूसरी तरफ, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने सरकार पर लोकतंत्र की अनदेखी करने और चुनावों से भागने का आरोप लगाते हुए 'हल्ला बोल' का ऐलान कर दिया है। हालांकि, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने दावा किया है कि सरकार और ओबीसी आयोग युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं और वर्ष 2026 के उत्तरार्ध में हर हाल में चुनाव करा लिए जाएंगे।

हाईकोर्ट की डेडलाइन : अदालत ने हर हाल में 31 जुलाई 2026 तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के सख्त निर्देश दिए थे।

टूटने की वजह: ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए आवश्यक डेटा की अनुपलब्धता और मानसून की शुरुआत।

मास्टरस्ट्रोक : चुनाव से पहले सरकार ने 76 नई नगरपालिकाएं गठित कर प्रशासनिक ढांचा बदला।

नई संभावित तिथि : जानकारों के अनुसार अब सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर में ही बज सकेगा चुनावी बिगुल।

खड़ी कार का एयरबैग खुलने से युवक की मौत

ठाणे

घटना बुधवार को ठाणे के काशिमीरा इलाके में हुई। जानकारी पुलिस ने शनिवार को दी है।

महाराष्ट्र के ठाणे में एक खड़ी कार में अचानक एयरबैग खुलने से 25 साल के कार डीलर की मौत हो गई। युवक का नाम मोहित सोनी है। वह एक 15 साल पुरानी कार के अंदर बैठा था। तभी अचानक गाड़ी का सेफ्टी सिस्टम एक्टिव हो गया। एयरबैग इतनी तेजी से खुला कि उसके जोरदार झटके से उसको गंभीर चोटें आईं। ज्यादा खून बहने के कारण उसकी मौत हो गई। युवक को चोट कहां लगी इसकी जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। यह घटना बुधवार को ठाणे के काशिमीरा इलाके में हुई। पुलिस ने जानकारी शनिवार को दी।

ठाणे पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में पता चला है कि कार भले ही पुरानी थी, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार उसके पास वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट था। पुलिस ने मामले में एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज किया है। पुलिस जांच के लिए ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स से भी सलाह ले रही है।

एयरबैग खुलने की स्पीड 200 से 300 किमी/घंटा के बीच हो सकती है। इस वजह से तेज झटका लगता है। इससे बचने के लिए सीट बेल्ट लगाना जरूरी होता है। सीट बेल्ट ना लगाने की स्थिति में जोरदार झटका लगने से गंभीर चोट लग सकती है या मौत भी हो सकती है।

शांति वार्ता के बीच अमेरिका ने ईरान के मिसाइल-ड्रोन ठिकानों पर किया हमला

ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, कहा- सीजफायर तोड़कर पछताएगा अमेरिका

तेहरान/वॉशिंगटन डीसी

मध्य पूर्व के सबसे संवेदनशील और रणनीतिक समुद्री मार्ग 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' में वैश्विक व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर सीधे युद्ध जैसी परिस्थितियां बन गई हैं। होर्मुज जलमार्ग से गुजर रहे एक कमर्शियल कार्गो शिप पर ईरानी सेना द्वारा किए गए हमले से बौखलाए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने शुक्रवार को एक अत्यंत आक्रामक और बड़ा सैन्य पलटवार किया है।

अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने ईरान की सीमाओं के भीतर घुसकर उसके कई संवेदनशील ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। इस भीषण एयरस्ट्राइक में मुख्य रूप से ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स, आत्मघाती ड्रोन स्टोरेज डिपो और तटीय इलाकों में तैनात कोस्टल

रडार सिस्टम को निशाना बनाकर पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया गया है।

अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के मुताबिक, 25 जून को ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में सिंगापुर के कार्गो शिप 'एमवी एवर लवली' पर ड्रोन हमला किया था।

दूसरी ओर, ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की नौसेना ने दावा किया है कि उसने जवाब में क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है

ईरान की संसद के सदस्य इब्राहिम अजीजी ने एक्स पर लिखा कि अमेरिका ने एक बार फिर बातचीत के बीच ईरान पर हमला किया है। युद्धविराम का यह उल्लंघन अमेरिका के लिए पीछे हटने और पछतावे की वजह बनेगा।

ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरानी सेना ने अमेरिका से जुड़े ठिकानों पर हमला किया है। मंत्रालय के मुताबिक यह कार्रवाई ईरान के दक्षिणी तटीय इलाकों पर हुए अमेरिकी हवाई हमलों के जवाब में की गई।

ट्रंप ने कहा- यह सीजफायर डील का मूर्खतापूर्ण उल्लंघन

सैन्य कार्रवाई के तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक के बाद एक कई पोस्ट कर इस हवाई हमले की पुष्टि की। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने अंतरराष्ट्रीय नियमों को ताक पर रखकर रणनीतिक जलमार्ग से शांतिपूर्वक गुजर रहे जहाजों पर बेहद खतरनाक 'वन-वे अटैक ड्रोन' दागे थे। ट्रंप ने ईरान के इस कदम को दोनों देशों के बीच हुए संघर्ष-विराम समझौते का बेहद मूर्खतापूर्ण और अक्षम्य उल्लंघन बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिकी हितों और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं और ईरान को उसकी इस हिमाकत की भारी विधिक व सैन्य कीमत चुकानी होगी।

महाराष्ट्र में एग्जाम से एक दिन पहले टीईटी पेपर लीक, परीक्षा रद्द

पेपर ठाणे से बरामद, सरकारी टीचर्स के लिए ये परीक्षा जरूरी

मुंबई

महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) का क्वेश्चन पेपर करीब 24 घंटे पहले लीक हो गया। एग्जाम रविवार को होना था। महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल ने इसके बाद परीक्षा स्थगित कर दी है। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा।

पुलिस के मुताबिक, क्वेश्चन पेपर लीक की सूचना के बाद ठाणे के भिवंडी इलाकों के कई जगहों पर छापेमारी की। इसके बाद एग्जामिनेशन काउंसिल के अफसरों को बुलाया और जब्त पेपर को वेरिफाई कराया गया

पुलिस ने बताया कि इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि संख्या नहीं बताई है। यह कार्रवाई एग्जाम के 24 घंटे पहले की गई। परीक्षा में 4.28 लाख ज्यादा उम्मीदवार शामिल होने वाले थे। महाराष्ट्र में टीचर बनने के लिए या

जो पहले से सरकारी टीचर हैं, उनके लिए भी टीईटी कंपलसरी है।

सुप्रीम कोर्ट ने 29 मई को आदेश दिया था कि स्कूलों में काम कर रहे शिक्षकों के लिए टीचर इलिजिबिलटी टेस्ट (टीईटी) पास करना अनिवार्य है। कोर्ट ने टीईटी पास करने की समय सीमा 31 अगस्त 2027 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दी।

हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसके बाद कोई और समय नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा, बिना टीईटी योग्यता वाले शिक्षक सेवा में बने रहे तो इसका असर आने वाली पीढ़ियों की शिक्षा पर पड़ेगा। फैसले का असर देश के 20 लाख से ज्यादा शिक्षकों पर होगा।

राजनीतिक बयान बाजी तेज

मामला प्रकाश में आने पर विपक्षी राजनीतिक दलों ने सरकार पर तीखा हमला किया। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (टीईटी) के पूर्व महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष ने एक्स पर लिखा, 'नीट पेपर लीक होने के बाद अब ठाणे में फिर से शिक्षक बनाने वाली टीईटी (टीईटी) परीक्षा का पेपर लीक हो गया। वाह रे भाजपा सरकार! पार्टी चुराते हो, सांसद चुराते हो, विधायक चुराते हो... अरे कम से कम बच्चों के पेपर तो छोड़ दो, वो तो मत चुराओ!'

मुंबई-मुहर्रम जुलूस में दर्द की दवा बताकर जहरीले कैप्सूल बांटे

मुंबई

मुंबई में मोहर्रम जुलूस के दौरान लोगों को जिंक फॉस्फाइड के जहरीले कैप्सूल बांटने का मामला सामने आया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक, आरोपी फैयाज प्रेमजी 'दर्द से राहत' के नाम पर लोगों को ये कैप्सूल देने की कोशिश कर रहा था। मामला मुंबई के जेजे और भायखला इलाके का है। जुलूस के दौरान आरोपी ने कई लोगों को ये कैप्सूल दिए थे। इनमें से एक शख्स का पेट दर्द और उल्टी होने लगी। इसके बाद लोगों को कुछ शक हुआ तो पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस ने आरोपी को 14,900 कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया। उसने हर कैप्सूल में करीब एक ग्राम जहर भरा था। इसके लिए 50 किलो जिंक फॉस्फाइड मंगाया था। आरोपी करीब 30 हजार जहरीले कैप्सूल बनाने की तैयारी में था। जिंक फॉस्फाइड का इस्तेमाल चूहे मारने वाली दवा बनाने के लिए किया जाता है।

भजनलाल सरकार का स्वस्थ पैकेज:हस्तशिल्प हाट, 25 स्टार्टअप्स को मदद, नई औद्योगिक नीति लॉन्च, 13 करोड़ के चेक बांटे

जयपुर

राजस्थान में पहली बार आयोजित हुए अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई), हस्तशिल्प, स्टार्टअप और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को नई गति देने के लिए कई अहम घोषणाएं की। जयपुर के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को 13 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऋण, अनुदान और सब्सिडी के चेक और रीको की योजनाओं के तहत भूमि आवंटन पत्र और ऑफर लेटर बांटे किए। साथ ही राजस्थान औद्योगिक विकास नीति, वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) कॉफी टेबल बुक और रैम्प (राइजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस) पोर्टल का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएसएमई प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और रोजगार सृजन के सबसे बड़े माध्यम हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने, स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने और विकास के साथ प्रदेश की विरासत को संरक्षित रखने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि आज राजस्थान में 33 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां कार्यरत हैं, जिससे प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा एमएसएमई राज्य बन चुका है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार उद्योगों और निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगातार नई नीतियां लागू कर रही है और राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट ने निवेशकों का भरोसा मजबूत किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उद्योगों के लिए भूमि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लागू डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी-2025 के तहत पिछले एक वर्ष में 1600 से अधिक औद्योगिक भूखंडों का आवंटन किया जा चुका है। इसके साथ ही उद्योगों से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए कई सुधार किए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में एमएसएमई इकाइयों के लिए लैंड यूज अप्रूवल की समय-सीमा 60 दिन से घटाकर 30 दिन कर दी गई है। वहीं उद्योग शुरू करने के लिए आवश्यक स्वीकृतियों का समय 120 दिन से घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की व्हाइट कैटेगरी भी 104 से बढ़ाकर 877 उद्योगों तक विस्तारित की गई है, जिससे हजारों उद्यमियों को राहत मिली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए राजस्थान में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क, सिरेमिक पार्क, डाटा सेंटर पार्क और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पार्क विकसित किए जा रहे हैं।

दिल्ली-एनसीआर और जम्मू-कश्मीर में भूकंप के तेज झटके

अफगानिस्तान में आए 6.2 तीव्रता के भूकंप का असर, 8 देशों में भी महसूस हुए झटके

श्रीनगर.

अफगानिस्तान के हिंदूकुश क्षेत्र में शनिवार शाम 7.04 बजे 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। इसका असर अफगानिस्तान समेत 8 देश भारत, पाकिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में देखा गया।

देश में जम्मू-कश्मीर और दिल्ली-एनसीआर में भी झटके महसूस किए गए। लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। हालांकि, अब तक किसी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है। इसका केंद्र उत्तर-पूर्वी

अफगानिस्तान में कलाफगान से करीब 81 किलोमीटर दूर था और गहराई 215द्वद्व थी।

श्रीनगर के रहने वाले इम्तियाज अहमद ने बताया कि वह घर के बाहर कुर्सी पर बैठे हुए थे। तभी कुर्सी और बिजली की तारें हिलने लगीं। वहीं स्टूडेंट वहीद ने कहा कि वह रास्ते में थे तभी उन्हें हल्के झटके महसूस हुए।

पिछले 24 घंटों में देश में 2, पाकिस्तान में 4 भूकंप आए

शनिवार सुबह 11:38 बजे हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में 3.2 तीव्रता का हल्का भूकंप आया था। इसका केंद्र जमीन से सिर्फ 5 किलोमीटर की गहराई पर था। इसका केंद्र धर्मशाला से करीब 22द्वद्व उत्तर-उत्तर-पश्चिम में था। यूरोपियन-भूमध्यसागरीय सिस्मो लॉजीकल सेंटर (श्वस्स्ष्ट) के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान में भी भूकंप के चार झटके महसूस किए गए, जिनमें सबसे तेज झटका 5.5 तीव्रता का था। सबसे तेज भूकंप शनिवार सुबह 8:36 बजे आया। इसकी तीव्रता 5.5 मापी गई, जो जमीन से 40 किलोमीटर की गहराई पर आया था। केंद्र पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में था। हादसे में 5 लोगों के घायल होने की खबर है। श्वस्स्ष्ट ने इन चारों भूकंपों की पुष्टि की है।

भूकंप तीव्रता 6.5 से ज्यादा होने पर नुकसान

जहां भूकंप का केंद्र होता है वहां तेज झटके महसूस किए जाते हैं। जैसे जैसे केंद्र से दूरी बढ़ती है उतने तेज झटके महसूस नहीं होते हैं। आमतौर पर भूकंप की तीव्रता 6.5 या उससे ज्यादा होने पर जान-माल के नुकसान की आशंका बढ़ जाती है। 6 या उससे कम तीव्रता का भूकंप आने पर लोगों और सामान्य जनजीवन पर कम असर होता है।

अफगानिस्तान में बार-बार भूकंप क्यों आते हैं?

अंतरराष्ट्रीय संगठन रेड क्रॉस के मुताबिक, अफगानिस्तान दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित देशों में से एक है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहां भारतीय (इंडियन) और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं। इस टक्कर से जमीन के अंदर लगातार दबाव बनता रहता है, जो समय-समय पर भूकंप के रूप में बाहर निकलता है। इसके अलावा अफगानिस्तान का हिंदूकुश पर्वतीय क्षेत्र कई सक्रिय भू-भ्रंश (फॉल्ट लाइन) पर स्थित है। इसलिए यहां अक्सर तेज और गहरे भूकंप आते हैं, जिनके झटके भारत, पाकिस्तान और मध्य एशिया के कई देशों तक महसूस होते हैं।

सम्पादकीय

"मानवता सुख शांति प्रेम का, अखिल विश्व में हो
विस्तारस्वतंत्रता का हनन न होवे, रहे सुरक्षित जन अधिकार"

नागरिकता का प्रमाण

विदेश मंत्रालय के स्पष्टीकरण के बाद पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण न मानने पर बहस छिड़ गई है।

विदेश मंत्रालय के इस स्पष्टीकरण ने कि पासपोर्ट यात्रा का दस्तावेज है, नागरिकता का प्रमाण नहीं, एक बहस को जन्म दे दिया है तो इसीलिए, क्योंकि आम धारणा यही थी कि पासपोर्ट नागरिकता का सबसे पुष्ट प्रमाण होता है। यह आम धारणा इसके बाद भी थी कि पासपोर्ट एक्ट ऐसा नहीं कहता। इस एक्ट के अनुसार विशेष परिस्थितियों में गैर-भारतीयों को भी पासपोर्ट जारी किया जा सकता है। उच्च न्यायालयों ने भी यही निर्णय दिया है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है। विदेश मंत्रालय के स्पष्टीकरण के बाद इस पर बहस होना स्वाभाविक है कि यदि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो फिर क्या है? यह प्रश्न इसलिए भी सतह पर है, क्योंकि हाल में और विशेष रूप से कुछ राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर के वक्त यह कहा गया कि आधार भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। इसी तरह पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड इत्यादि भी नागरिकता के प्रमाण पत्र नहीं माने गए। यह सही है कि नागरिकता का निर्धारण सिटिजनशिप एक्ट के तहत होता है, लेकिन समस्या यह है कि देश के लोगों को किसी तरह का नागरिकता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता। सिटिजनशिप एक्ट यह तो बताता है कि जन्म, वंश, देश में लंबी अवधि तक रहने और कुछ अन्य आधारों पर नागरिकता तय होती है, लेकिन अपने देश में अन्य देशों की तरह नागरिकता का कोई विशिष्ट प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता। विश्व के विकसित और यहां तक कि कई विकासशील देशों में यह काम किया जाता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि इन देशों के लोगों को अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए तरह-तरह के दस्तावेजों का सहारा नहीं लेना पड़ता। चूंकि सिटिजनशिप एक्ट इसकी सिफारिश करता है कि भारत सरकार प्रत्येक नागरिक का अनिवार्य पंजीकरण कर सकती है, राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी कर सकती है और अपने नागरिकों का रजिस्टर यानी एनआरसी तैयार कर सकती है, इसलिए यह काम किया ही जाना चाहिए। हालांकि अतीत में नागरिकता प्रमाण पत्र के लिए एनआरसी लाने और आधार को एनआरसी से जोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ हो नहीं सका। इसके बाद नागरिकता कानून में संशोधन करने यानी सीएए बनाने के बाद एनआरसी की आवश्यकता जताई गई, लेकिन उसके खिलाफ दुष्प्रचार के तहत एक अभियान छेड़ दिया गया। इससे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर तैयार करने की पहल ठंडे बस्ते में चली गई। अभी तक केवल असम में नागरिक रजिस्टर तैयार किया जा सका है। उचित यह होगा कि शेष देश में भी ऐसा ही किया जाए और एनआरसी तैयार कर लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र दिए जाएं। यह पहल घुसपैठियों की पहचान करने के साथ कई अन्य समस्याओं का भी समाधान करेगी।

लखनऊ जैसे हादसे चिंताजनक परिपाटी का संकेत दे रहे हैं

हादसे छोटे हों या बड़े – किसी भी मामले में अगर कोताही न बरती जाए, नियमों को लेकर सख्ती की जाए, तो काफी हद तक ऐसे हादसों को टाला जा सकता है। जरूरत गंभीरता से कार्रवाई करने की है।

जैसे ही कोई हादसा होता है, धड़ाधड़ सूचनाएं आने लगती हैं कि कैसे नियमों के अनुपालन में कोताही बरती गई और सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देशों की अनदेखी की गई। भवन निर्माण की मंजूरी, सुरक्षा मानकों के अनुपालन, निरीक्षण तंत्र, अग्नि सुरक्षा मंजूरी और विभिन्न विभागों की लापरवाही को लेकर असंख्य तथ्य सामने आने लगते हैं। लखनऊ के अलीगंज हादसे को लेकर भी खबरें आ रही हैं। नियमों के अनुपालन में सख्ती के दावे अधिकारी कर रहे हैं। कई स्तर पर कार्रवाई की सूचनाएं प्रशासन जारी कर रहा है। अहम सवाल है कि अगर खामियों के बारे में पहले से सब कुछ पता रहता है, तो किस मजबूरी में प्रशासन ने इस मामले में अब तक आंखें बंद कर रखी थीं? ऐसे हादसों में नियमों के उल्लंघन को लेकर सवाल उठते हैं। कुछ दिनों तक जांच चलती है और खामोशी छा जाती है। जांच में ऐसी कोताही अस्वीकार्य होनी चाहिए। दरअसल, इस तरह के हादसे मौजूदा दौर में सेवा क्षेत्र के इर्द-गिर्द फलती-फूलती शिक्षा अर्थव्यवस्था, अनियोजित शहरी विस्तार और नियमन की विफलताओं को प्रतिबिंबित करते हैं। कम पूंजी निवेश में मोटे मुनाफे के लालच में नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। ऐसे उल्लंघन पूरे भारत में आम हैं, जहां व्यावसायिक और शैक्षिक प्रतिष्ठान बुनियादी सुरक्षा मानदंडों की अनदेखी कर रहे हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के जो तथ्य सामने आए हैं, उनसे पता चलता है कि लगभग एक दशक पहले कथित अनधिकृत निर्माण के आरोप में अलीगंज की संपत्ति को गिराने की कार्रवाई शुरू की गई थी। इसे एलडीए आवास योजना के तहत आबंटित किया गया और बाद में बेचा गया था। इसे 2014 में आवासीय संरचना के रूप में मंजूरी दी गई थी। एलडीए ने अवैध निर्माण का पता चलने पर मई 2016 में गिराने का आदेश जारी किया, लेकिन दो महीने के भीतर ही आदेश वापस ले लिया। इन सवालों के जवाब सामने नहीं आए हैं कि विध्वंस के आदेश पर अमल क्यों नहीं हुआ? इसे वापस क्यों लिया गया? लखनऊ जैसे हादसे एक चिंताजनक परिपाटी का संकेत दे रहे हैं। अधिकांश योजनाओं और भवन उपनियमों में मिश्रित उपयोग वाले निर्माण की अनुमति दी जाती है, बशर्ते ऐसी इमारतें अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन करती हों। लखनऊ के हादसे से स्पष्ट है कि दशकों तक गैर-कानूनी तरीके से आवासीय इमारत में कोचिंग संस्थान और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां चलती रहीं और प्रशासन सोता रहा। आए दिन होने वाले अग्निकांड से कोई सबक नहीं सीखा गया। प्रत्येक आपदा से मिलने वाले सबक सीमित रह जाते हैं। घटना के तुरंत बाद इमारत को सील करने और नोटिस देने का जो सिलसिला शुरू होता है, वह महज एक नियमित प्रक्रिया है। जांच की कवायद कुछ दिनों बाद ठंडे बस्ते में चली जाती है। बीते कुछ महीनों में कोचिंग संस्थानों, होटलों और इसी तरह के प्रतिष्ठानों में लगी आग की कई घटनाएं सामने आई हैं। व्यापक रूप से चर्चा उन हादसों को लेकर हुई है, जिनमें जान-माल का नुकसान हुआ। हादसे छोटे हों या बड़े ङ्क किसी भी मामले में अगर कोताही न बरती जाए, नियमों को लेकर सख्ती की जाए, तो काफी हद तक ऐसे हादसों को टाला जा सकता है। जरूरत गंभीरता से कार्रवाई करने की है।

बच्चों के सीखने का जरिया हैं खेल

हर बचपन कुछ जानी-पहचानी आवाजों से गूंजता है। धूल भरे मैदानों पर गेंद के गिरने की धमक। तंग गलियों में दौड़ते बच्चों की हंसी। रस्सी कूदने की लय, कंचों की खनक और ढेर सारे गीत-कहानियां। खेल-खेल में बच्चों की दुनिया को समझना ही सीखने की प्रक्रिया की सबसे पहली शुरुआत है। मुझे याद है, जब मैं छोटा था, तो घंटों अपने कोच की देखरेख में खेला करता था। वे स्टंप्स पर एक रुपये का सिक्का रख देते थे और गेंदबाजों को मुझे आउट करने की चुनौती देते थे। अगर वे मुझे आउट कर देते, तो सिक्का उनका और अगर मैं नाबाद रहता, तो वह मेरा होता। वे सिक्के आज भी मेरी सबसे अनमोल धरोहर हैं। उन्होंने मुझे एकाग्रता, धैर्य और खुद को बेहतर बनाने का दृढ़ संकल्प सिखाया। स्कोरबोर्ड, बड़े स्टेडियमों और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की दुनिया में पहुंचने से बहुत पहले, मैंने खेल के जरिये ही सब कुछ सीखा। नेतृत्व को समझने से पहले मैंने टीम के साथ मिलकर काम करना सीखा। खेल में हारकर मैंने मुश्किलों से उबरना सीखा और बार-बार कोशिश करके आत्मविश्वास बढ़ाया। दुनिया भर के लाखों बच्चों की तरह मैंने भी यह महसूस किया कि खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि यह खुद जीवन की तैयारी है। यूनिसेफ के साथ जुड़ने के बाद मुझे लगता है कि यह संदेश पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। आज पूरी दुनिया में बचपन बदल रहा है। खुले मैदान कम हो रहे हैं। पढ़ाई के बढ़ते बोझ और आनलाइन बिताए जाने वाले समय की वजह से बच्चों के लिए खुलकर खेलने, खुलकर कल्पना करने और आपस में मिलने-जुलने

ऐसा करके हम केवल बचपन को सुरक्षित ही नहीं करते, बल्कि हम सभी के लिए एक स्वस्थ, खुशहाल और उम्मीदों से भरे भविष्य का निर्माण करने में मदद करते हैं।

के अवसर कम होते जा रहे हैं। न्यूरोसाइंस और सीखने का विज्ञान पुष्टि करते हैं कि जब बच्चे खेलते हैं, तो वे जीवनभर के लिए सीखते हैं। खेल के जरिये वे भाषा सीखते हैं, अपनी एकाग्रता बढ़ाते हैं, भावनाओं पर काबू पाना सीखते हैं, समस्याओं को सुलझाने का अभ्यास करते हैं और दूसरों के साथ घुलना-मिलना सीखते हैं। जीवन के पहले आठ साल मानव विकास के सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से हैं। इन वर्षों के दौरान मस्तिष्क का विकास जीवन के किसी भी अन्य चरण की तुलना में सबसे तेजी से होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के नर्चरिंग केयर फ्रेमवर्क के शोध से पता चलता है कि मस्तिष्क का 85 प्रतिशत से अधिक विकास छह साल की उम्र से पहले ही हो जाता है। यही शुरुआती साल शारीरिक स्वास्थ्य, भावनात्मक सुरक्षा, भाषा, जिज्ञासा, आत्मविश्वास और सामाजिक समझ की नींव रखते हैं। यही वे वर्ष हैं, जब बच्चों में सुनने, संवाद करने, ध्यान केंद्रित करने, याद रखने, तर्क करने और पढ़ने-लिखने और गणित की बुनियादी समझ जैसी महत्वपूर्ण क्षमताएं विकसित होती हैं। इसी दिशा में भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति छोटे बच्चों के लिए खेल-आधारित शिक्षा के महत्व को स्वीकार करती है। यह सोच में आया एक बड़ा बदलाव है, जो आंगनवाड़ी और शुरुआती कक्षाओं में खेल को बुनियादी शिक्षा का केंद्र बनाता है। अब कक्षाएं तेजी से ऐसी बनती जा रही हैं, जहां बच्चे गतिविधियों और खेल-खेल में सीखते हैं। जब गणित के जोड़ को कंचों के साथ खेल-खेल में सिखाया जाता है, तो वह मजेदार हो जाता है। इसी तरह, रोल-प्ले (नाट्य रूप) के जरिये भाषा और आत्मविश्वास बढ़ता है और अपने आसपास की दुनिया को देखकर आकृतियों और रंगों की समझ बेहतर होती है। गीत, कहानियां और शारीरिक गतिविधियां पाठों में जान डाल देती हैं, जिससे कक्षाएं जिज्ञासा, सहभागिता और सीखने के उत्साह से भरी जीवंत जगह बन जाती हैं। खेल-खेल में सीखने का सिलसिला स्कूल के बाद भी जारी रहता है-चाहे घर पर हो, गलियों में हो या खेल के मैदान में। इसके लिए महंगे खिलौनों या बड़े बुनियादी ढांचे की जरूरत नहीं होती। एक मां का बच्चे को खाना खिलाते हुए लोरी सुनाना, दादाजी का पेड़ के नीचे बैठकर कहानियां सुनाना, भाई-बहनों का घर की चीजों से नए खेल खेलना या पिता का अपने बच्चे के साथ टहलते हुए उसे पक्षियों, रंगों और आवाजों के बारे में बताना-ये सभी सीखने के बेहतरीन अवसर हैं। इन पलों में बच्चे अपनी शब्दावली, एकाग्रता, याददाश्त, कल्पना और आपसी रिश्तों को मजबूत करते हैं। यही वह बुनियाद है, जिस पर आगे की शिक्षा टिकी होती है। अगर हम चाहते हैं कि बच्चे सही मायने में विकसित हों, तो खेल को केवल एक विकल्प नहीं रहने दिया जा सकता। हमें इसे सुरक्षित रखना होगा, बढ़ावा देना होगा और हर बच्चे के जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाना होगा-घर में भी और स्कूल में भी। यह हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें बचपन को उसी रूप में देखना होगा, जैसा वह वास्तव में है। एक आनंदमय और कीमती पड़ाव, जिसे देखभाल, सुरक्षा और आगे बढ़ने के अवसरों की जरूरत है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसका जीवन खेलकूद के जरिये गहराई से संवरा है, मैं इसकी शक्ति को भलीभांति समझता हूं। आइए, हम सब मिलकर एक सचेत निर्णय लें। बच्चों को खेलने, नई चीजें खोजने और बस बच्चे बने रहने का समय, स्थान और भरोसा दें। ऐसा करके हम केवल बचपन को सुरक्षित ही नहीं करते, बल्कि हम सभी के लिए एक स्वस्थ, खुशहाल और उम्मीदों से भरे भविष्य का निर्माण करने में मदद करते हैं।

कल्याणकारी योजनाओं से वंचित वर्ग का सशक्तिकरण

ए. सूर्यप्रकाश

भारत की शासन व्यवस्था से परिचित लोग यह कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी सक्षम नेतृत्वकर्ता सिद्ध हुए हैं। उनके नेतृत्व में बीते 12 वर्षों के दौरान भारत ने अद्भुत प्रगति की है। बुनियादी ढांचे से लेकर गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य देखभाल, उद्योग, कृषि, विदेश नीति, रक्षा और डिजिटल इंडिया हो या सामाजिक क्षेत्र में हासिल उपलब्धियां इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इन्हीं उपलब्धियों के दम पर वे भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। उनकी सफलताओं की सूची को एक स्तंभ में समेटना बहुत मुश्किल है। ऐसे में सर्वाधिक उल्लेखनीय पहलू को रेखांकित करना ही सबसे उचित होगा, जिसने उनकी एक अलग पहचान बनाई। मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही गरीब और हाशिए पर मौजूद वंचित वर्गों को अपनी प्राथमिकता बनाया और उनके उत्थान के लिए ऐसी योजनाएं बनाकर उन्हें धरातल पर उतारा, जिससे इन वर्गों के जीवन की गुणवत्ता सुधरी है। उनके नेतृत्व में की गई कई पहल संविधान के भाग चार में उल्लिखित राज्य नीति के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत उन उद्देश्यों से ही प्रेरित हैं, जो कल्याणकारी राज्य बनाने और विशेष रूप से गरीबों के लिए जीवन को सुगम बनाने का प्रयास करती हैं। मोदी की पहली क्रांतिकारी पहल थी प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसने वित्तीय समावेशन में एक नई क्रांति की। इसका यह बिंदु और भी संतोषजनक है कि जनधन में 56 प्रतिशत खाताधारक महिलाएं हैं। इसने देश की आधी आबादी के लिए वित्तीय स्वतंत्रता की राह प्रशस्त की है। इसी क्रम में मोदी का अगला बड़ा विचार था स्वच्छ भारत मिशन। इसके अंतर्गत गरीब परिवारों को शौचालयों के निर्माण के लिए सब्सिडी प्रदान की गई। ऐसा ही एक कार्यक्रम रहा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों को सब्सिडी वाली रसोई गैस उपलब्ध कराना था। इस योजना के जरिये 10.5 करोड़ परिवार लाभार्थी बने हैं। यह सही है कि पश्चिम एशिया युद्ध के कारण सब्सिडी वाले सिलिंडरों की संख्या में कटौती की गई, लेकिन उम्मीद है कि जब पेट्रोलियम उत्पादों का प्रवाह सामान्य होगा, तो इसे बहाल किया जाएगा। हर घर नल से जल कार्यक्रम भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जिसका उद्देश्य सभी ग्रामीण परिवारों को पाइप से पानी की आपूर्ति करना है। अब तक 19 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 73 प्रतिशत के पास यह सुविधा पहुंचाई जा चुकी है। कोविड काल में संघर्ष कर रहे लोगों को सहारा देने के लिए आरंभ की गई मुफ्त राशन योजना भी 81 करोड़ लोगों का सहारा बन चुकी है। इस योजना ने मुश्किल वक्त में गृहिणियों के समक्ष चुनौतियों

विरोधियों की इस बात में कुछ तर्क हो सकता है कि प्रधानमंत्री देश में सामाजिक तनावों को पूरी तरह से सुलझा नहीं पाए हैं। देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं के रवैये को लेकर भी उनकी कुछ शिकायतें जायज हो सकती हैं।

को विकराल नहीं होने दिया। इन सभी योजनाओं का मर्म समझें तो इनकी संकल्पना कहीं न कहीं महिलाओं की मुश्किलों को ध्यान में रखकर की गई। जैसे गरीब ग्रामीण परिवारों में महिलाओं को शौच के लिए घर से बाहर और अक्सर गांव से बाहर तक जाना पड़ता था। शौचालय की सुविधा से उन्हें बड़ी राहत मिली। चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने के लिए दूर-दराज जाना पड़ता था और धुएं में खाना पकाना पड़ता था, लेकिन रसोई गैस से उनकी ये दुश्वारियां दूर होने के साथ ही भोजन पकाना भी कहीं आसान हो गया है। सरकार ने विधानसभाओं और संसद में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों के आरक्षण के लिए कानून को आगे बढ़ाने की भली मंशा दिखाने के साथ ही सशस्त्र बलों में महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षित 17 महिला अधिकारियों का पहला बैच हाल ही में सशस्त्र बलों में कमीशन किया गया। महिलाओं के मुद्दों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता का सबसे अच्छा उदाहरण 2017 में मातृत्व लाभ अधिनियम में संशोधन और महिलाओं के लिए पहले दो बच्चों के लिए मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने का निर्णय रहा है। यह प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं की रोजगार और वेतन की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे में यह कहना सर्वथा उचित होगा कि महिलाओं का सशक्तीकरण मोदी सरकार की नीतियों का आधार रहा है। इन योजनाओं को व्यापक संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये राज्य के नीति निदेशक तत्वों की अनुशंसाओं से प्रेरित हैं। जैसे कि संविधान का अनुच्छेद 42 उचित और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत प्रदान करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 43 एक निर्वाह योग्य पारिश्रमिक और सम्मानजनक जीवन स्तर सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। वहीं, अनुच्छेद 47 राज्य को सभी नागरिकों के लिए विशेष रूप से पोषण के अपेक्षित स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का स्पष्ट निर्देश देता है। इसलिए, चाहे 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की आपूर्ति हो, गरीबों और बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा, महिलाओं के लिए छह महीने का मातृत्व अवकाश, घरों में शौचालयों के निर्माण के लिए सब्सिडी या जन धन योजना हो, ये सभी संविधान द्वारा सुझाई गई राह के अनुरूप ही हैं। विरोधियों की इस बात में कुछ तर्क हो सकता है कि प्रधानमंत्री देश में सामाजिक तनावों को पूरी तरह से सुलझा नहीं पाए हैं। देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं के रवैये को लेकर भी उनकी कुछ शिकायतें जायज हो सकती हैं। ये भी ऐसे गंभीर मुद्दे हैं, जिन पर प्रधानमंत्री को समय के साथ ध्यान देना ही होगा। इसके बावजूद, विभिन्न क्षेत्रों में उनकी अभूतपूर्व उपलब्धियों का उन्हें श्रेय न देना संकीर्ण मानसिकता का उदाहरण ही कहा जाएगा। उनके नेतृत्व में भारत के वैश्विक पटल पर बढ़ रहे मान-सम्मान को देखते हुए भी उनका अंधविरोध स्वयं कमजोर पड़ जाता है। भारत का सर्वांगीण विकास आज हर क्षेत्र में स्पष्ट दिख रहा है, जिसकी चाहकर भी अनदेखी नहीं की जा सकती। इस वास्तविकता को झुठलाने वाले लोग स्वयं को ही अंधकार में रखने पर तुले हैं। देश की जनता आज एक नए और विकसित भारत में जी रही है।

असुरक्षित दिल्ली: नाबालिगों में हिंसक प्रवृत्ति का बढ़ना पूरे समाज के लिए चेतावनी

हम किशोरों को सामाजिक मूल्यों का पाठ नहीं पढ़ा पाए हैं। नाबालिगों में हिंसक प्रवृत्ति का बढ़ना पूरे समाज के लिए चेतावनी है। इसे रोकने के लिए कई स्तरों पर कदम उठाने की जरूरत है।

आज हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां चंद रुपये के लिए किसी की हत्या कर दी जाती है। यह कानून व्यवस्था का मसला जरूर है, लेकिन इसके समाजशास्त्रीय पक्ष को लगातार अनदेखा किया गया है। चिंता की बात है कि बच्चों का स्वभाव भी अब उग्र होता जा रहा है। मामूली बातों पर आपा खो देना सामान्य बात हो गई है। दिल्ली में एक बार फिर महज कुछ रुपये के लिए एक व्यक्ति की हत्या समाज की मनोदशा की स्याह तस्वीर सामने रखती है। खबरों के मुताबिक, पिछले दिनों राजधानी के तिलक नगर इलाके में मात्र डेढ़ सौ रुपये के विवाद में तीन नाबालिगों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी। नाबालिगों में इस तरह बढ़ रहे दुस्साहस की वजह जानने की आवश्यकता है। दिल्ली में स्थानीय निकाय से लेकर राज्य और केंद्र तक- तीन इंजन की सरकार होने और पुख्ता सुरक्षा के दावों के बीच इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर यहां पढ़ने-लिखने की उम्र में बच्चे हथियार लेकर चल रहे हैं, यह कानून व्यवस्था संभालने वालों की भी लापरवाही है। इस तरह के अपराध से नागरिकों के मन में असुरक्षा का बोध बढ़ेगा। वैसे भी आत्मकेंद्रित हो रहे समाज में अब कोई किसी को बचाने के लिए आगे नहीं आता। हालांकि तिलक नगर में हुई हत्या के मामले में आरोपी तीन किशोरों को दिल्ली पुलिस ने कुछ ही घंटे में पकड़ लिया, लेकिन सवाल है कि नाबालिगों के हाथों में चाकू जैसे घातक हथियार कैसे पहुंच रहे हैं? गौरतलब है कि दिल्ली में पहले भी इसी तरह महज चार सौ रुपये के लेनदेन के विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई थी। ताजा मामले में बताया गया कि पीड़ित ने जबरन एक किशोर से डेढ़ सौ रुपये लिए थे, जिसे वह वापस नहीं कर रहा था। इस तरह की घटनाओं से स्पष्ट है कि हम किशोरों को सामाजिक मूल्यों का पाठ नहीं पढ़ा पाए हैं। नाबालिगों में हिंसक प्रवृत्ति का बढ़ना पूरे समाज के लिए चेतावनी है। इसे रोकने के लिए कई स्तरों पर कदम उठाने की जरूरत है।

बच्चियों की आशा और समाजिक-धार्मिक बंदिशें

कुछ दिनों पहले भारत में एक नारा उछला था, 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'। इससे एक बात स्पष्ट होती है, बेटियों का जीवन खतरे में है। नारे का दूसरा हिस्सा बेटियों को शिक्षित करने से संबंधित है। इससे समाज का बेटियों के प्रति नजरिया पता चलता है। क्यों हमें ऐसे नारे की आवश्यकता पड़ती है? समाज-परिवार बेटे-बेटियों में फर्क करता है, यह सबकी जानी-देखी रोज की हरकत है। अगर भारत के बाहर नजर डालें तो बेटे-बेटियों के बीच किया गया फर्क दुनिया के अधिकांश समाज में दिखता है। इसकी जांच हम कुछ फिल्मों के माध्यम से कर सकते हैं। भारत के बाहर की दो फिल्मों के द्वारा यह देखने का प्रयास करती हूं। फिल्में ली हैं, जिन्हें बनाने वाले पुरुष नहीं बल्कि औरतें हैं, बनाने वाली बूढ़ी औरतें नहीं हैं, युवा स्त्रियां हैं और इन फिल्मों की केंद्रीय पात्र लड़कियां ही हैं। ऐसी बच्चियां जिन्हें अपनी छोटी-छोटी आशाओं-इच्छाओं के लिए समाज से टकराना पड़ता है। समाज इनके रास्ते में तमाम रोड़े अटकाता है। ग्यारह वर्ष की वाजदा (वाद मोहम्मद) की एक छोटी-सी इच्छा है। वाजदा साइकिल खरीद कर पड़ोसी अब्दुल्ला (अब्दुल्ला रहमान अल्गोहानी) को साइकिल रेस में हराना चाहती है। दूसरी ओर उससे छोटी छ: साल की बख्ते (निक्बख्त नौरोज) स्कूल जाकर मजेदार कहानियां सीखना चाहती है। यहां उसका हम उम्र अब्बास (अब्बास अलिजोमे) स्कूल जाता है। पहली कहानी सऊद अरबिया के रियाद में घटित हो रही है, दूसरी का कथानक अफगानिस्तान में स्थापित है। पहली फिल्म 'वाजदा' की निर्देशिका 40 साल की हैफा अल-मंसूर है, जो सऊदी अरबिया की रहने वाली हैं। दूसरी फिल्म की निर्देशिका ने 'बुद्धा कोलापस्ड आउट ऑफ शेम' फिल्म बनाने तक 20 साल पूरे नहीं किए थे। हाना मखमलबाफ ईरान की पैदाइश हैं। दोनों ने अपनी फिल्म में अपने अनुभव भी पिरोए हैं। हैफा के लिए शूटिंग कठिन रही, हाना के लिए भी आसान न रही होगी। लड़की की जिंदगी में पिता की अहम भूमिका होती है। वह उसका पहला आदर्श पुरुष होता है। दोनों फिल्मों में पिता तकरीबन गायब है जबकि दोनों निर्देशिकाएं अपने पिता की सहायता एवं प्रेरणा-प्रभाव से इस मुकाम तक पहुंची हैं। हैफा कवि अब्दुल रहमान मंसूर की बेटी हैं जिन्हें उनके पिता ने सिनेमाघर के अभाव में वीडियो पर फिल्म दिखाई और वे फिल्म स्टडी हेतु सिडनी गईं। हाना प्रसिद्ध ईरानी निर्देशक मोहसिन मखमलबाफ की छोटी बेटी हैं। उनका पूरा परिवार पिता-मां, सौतेली-मौसेरी बहन, भाई सब फिल्म बनाते हैं। उन्होंने फिल्म बनाने की व्यावहारिक शिक्षा अपने पिता से ली है। दोनों की यह पहली फिल्म है। वाद मोहम्मद की भी पहली फिल्म है, बख्ते गैर-पेशेवर बच्ची है। धनी घर की वाजदा तथा गरीब बख्ते दोनों मासूम, बुद्धिमान, संवेदनशील और लगन की पक्की हैं। वाजदा लड़कियों के स्कूल जाती है, बख्ते स्कूल जाने की हर संभव कोशिश कर रही है। दोनों बड़े लड़के प्यारे हैं और अपनी दोस्त के साथ हैं, अब्दुल्ला की शरारत वाजदा को साइकिल खरीदने की जिद को जुनून तक ले जाती है। बख्ते में अब्बास को पढ़ते देख स्कूल जाने की इच्छा पैदा होती है। पिता की अनुपस्थिति में साइकिल कैसे आए, बख्ते के घर में खैर कुछ नहीं ही है। वह स्कूल केलिए कॉपी-पेंसिल कहां से लाए। दोनों तमाम तरीके आजमाती हैं। वाजदा प्रतियोगिता जीतने केलिए कुरान रट रही है ताकि ईनाम की रकम से साइकिल खरीद सके, डर है तब तक साइकिल बिक न जाए। प्रतियोगिता जीतने के बाद भी रकम उसके हाथ नहीं लगती है। बख्ते चार अंडे बेच कर कॉपी खरीदने वाली है, मां की लिपस्टिक से पेंसिल का काम लिया जा सकता है। दोनों के लिए यह कठिन डगर है, बख्ते के लिए जीवन की बाजी लगाना है, क्योंकि वह तालिबान शासित देश में रह रही है। धार्मिक कट्टरता रियाद में भी है। लड़कियों-औरतों को शरीर ढक कर रहना है, लड़कों के साथ भिन्न व्यवहार दोनों जगहों पर है। वाजदा की मां बेटा पैदा नहीं कर पाई इसलिए उसका पिता दूसरी शादी कर रहा है, उसकी दादी अपने बेटे के पक्ष में है। 'वाजदा' का स्क्रीनप्ले हैफा मंसूर ने स्वयं तैयार किया जबकि हाना की फिल्म का स्क्रीनप्ले उनकी मां मारजीह मखमलबाफ ने लिखा है। 'वाजदा' की सिनेमाटोग्राफी लुट्ज़ रेटमीयर की है, 'बुद्धा कोलापस्ड आउट ऑफ शेम' का कैमरा उस्ताद अली ने संभाला है। पहली फिल्म 2012 में वेनिस फिल्म समारोह में दिखाई गई, फिल्म सर्वोत्तम विदेशी फिल्म का पुरस्कार ले आई। वैसे कुल 22 पुरस्कार मिले। यह सऊदी अरबिया की पहली फिल्म थी जिसे ऑस्कर के लिए भेजा गया था। 'बुद्धा कोलापस्ड आउट ऑफ शेम' को कुल आठ पुरस्कार मिले, सारे-के-सारे हाना मखमलबाफ को प्राप्त हुए। बच्चे सब देखते हैं, भले सब समझते नहीं हैं। बड़ों की कई बातें आत्मसात कर लेते हैं, जैसे अफगानिस्तान में कुछ लड़के स्कूल जाते हैं, बहुत सारे लडकों ने तालिबानी जीवन शैली अनजाने में अपना ली है। वे लड़की के खुले बाल, लिपस्टिक सहन नहीं कर सकते हैं। किसी को नापसंद करने पर उसे अमेरिकी जासूस कह सकते हैं, भले वह छ: साल की बच्ची हो। कब्र खोद कर दफनाने, संगसारी करना, टहनी से बंदूक बना कर गोली चलाने का काम कर सकते हैं। अब्दुल्ला वाजदा का दुपट्टा खींच सकता है। दोनों फिल्मों में कट्टरपंथ, पितृसत्तात्मकता, अत्याचार, हिंसा और बहुत कुछ है। हां, इन्हीं दकियानूसी समाज में आज की पीढ़ी के कुछ संवेदनशील, सकारात्मक व्यवहार वाले लड़के हैं।

हवा में जहर, शरीर पर वार: रोग-प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर रहा वायु प्रदूषण

वायु प्रदूषण अब सिर्फ दिल और फेफड़ों को ही नहीं, बल्कि हमारे इम्यून सिस्टम को भी कमजोर कर रहा है। कनाडा के एक अध्ययन में पाया गया है कि प्रदूषित हवा में मौजूद पीएम2.5 कण शरीर में ऐसे बदलाव ला सकते हैं, जो ल्यूपस जैसी ऑटोइम्यून बीमारियों का कारण बन सकते हैं। ऑटोइम्यून डिजीज का मतलब ऐसी बीमारियों से है जिनमें हमारे शरीर की सुरक्षा प्रणाली गलती से अपने ही शरीर पर हमला करने लगती है। यह अध्ययन 3,500 से अधिक लोगों के रक्त के नमूनों पर आधारित है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना द्वारा किए एक अन्य अध्ययन में सामने आया था कि लम्बे समय तक वायु प्रदूषण के संपर्क में रहने से रूमेटाइड अर्थराइटिस यानी गठिया का जोखिम 40 फीसदी तक बढ़ सकता है। वायु प्रदूषण अब सिर्फ दिल और फेफड़ों को ही नुकसान नहीं पहुंचा रहा, यह हमारे इम्यून सिस्टम को भी चुनौती दे रहा है। एक नई वैज्ञानिक पड़ताल ने वायु प्रदूषण और शरीर की रोग-प्रतिरोधक प्रणाली (इम्यून सिस्टम) के बीच खतरनाक कड़ी को उजागर किया है। अध्ययन के मुताबिक, प्रदूषित हवा में मौजूद बेहद महीन कण (पीएम2.5) शरीर में ऐसे बदलाव ला सकते हैं, जो आगे चलकर ल्यूपस जैसी ऑटोइम्यून बीमारियों की वजह बन सकते हैं। ऑटोइम्यून डिजीज का मतलब ऐसी बीमारियों से है जिनमें हमारे शरीर की सुरक्षा प्रणाली गलती से अपने ही शरीर पर हमला करने लगती है। आमतौर पर हमारा इम्यून सिस्टम शरीर को बैक्टीरिया, वायरस और अन्य हानिकारक चीजों से बचाता है। लेकिन इन बीमारियों में यह सिस्टम स्वयं अपनी ही कोशिकाओं और अंगों को नुकसान पहुंचाने लगता है। अपने इस अध्ययन में कनाडा की मैकगिल यूनिवर्सिटी से जुड़े शोधकर्ताओं ने ओंटारियो प्रांत के आंकड़ों का

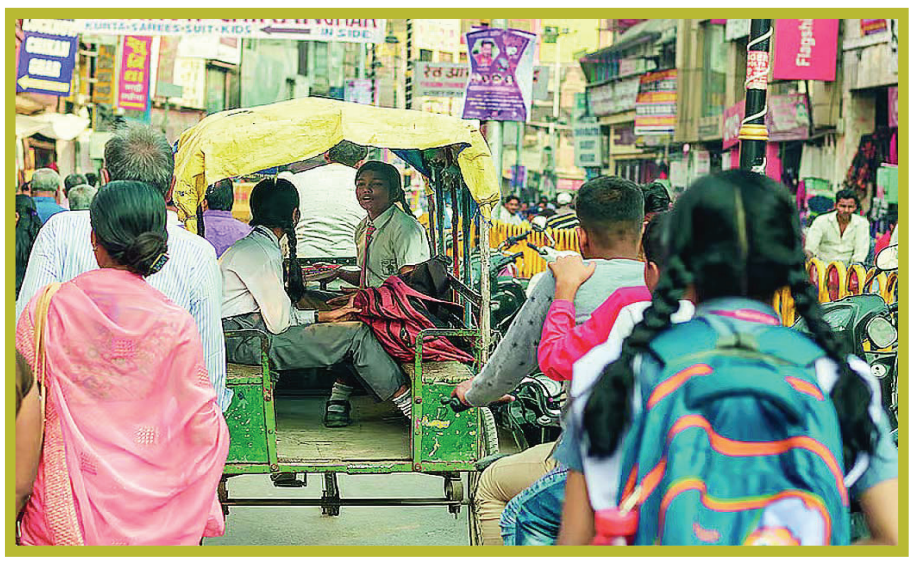

विश्लेषण किया है। उन्होंने पाया कि जिन इलाकों में हवा ज्यादा प्रदूषित थी, वहां रहने वाले लोगों के खून में एक खास बायोमार्कर %एंटी-न्यूक्लियर एंटीबॉडी (एएनए)% की मात्रा अधिक पाई गई। यह बायोमार्कर ल्यूपस जैसी कई ऑटोइम्यून बीमारियों से जुड़ा माना जाता है। मैकगिल सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ की सदस्य और अध्ययन से जुड़ी प्रमुख शोधकर्ता डॉक्टर साशा बर्नेट्स्की का प्रेस विज्ञप्ति में कहना है, अब तक माना जाता था कि ऑटोइम्यून बीमारियों में जेनेटिक कारण अहम हैं, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। नतीजे दर्शाते हैं कि वायु प्रदूषण इम्यून सिस्टम को इस तरह से प्रभावित कर सकता है, जो बीमारी की ओर ले जाए।

रक्त तक पहुंच जाते हैं प्रदूषण के कण: शोध के मुताबिक, पीएम2.5 जैसे महीन कण इतने छोटे होते हैं कि वो सांस के जरिए फेफड़ों से होते हुए सीधे रक्त में पहुंच सकते हैं। एक बार रक्त प्रवाह में पहुंचने के बाद ये पूरे शरीर को प्रभावित कर सकते हैं, यानी कि वायु प्रदूषण का असर सिर्फ दिल और फेफड़ों तक सीमित नहीं है। यह अध्ययन कैनपाथ नामक नेशनल रजिस्ट्री के तहत शामिल 3,500 से अधिक लोगों के रक्त के नमूनों पर आधारित है। इस रजिस्ट्री में कनाडा के 4 लाख से ज्यादा लोग शामिल हैं।

प्रदूषण अब सिर्फ शहरों की समस्या नहीं: शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में यह भी चेताया है कि वायु प्रदूषण को केवल शहरों और ट्रैफिक से जोड़कर देखना गलत है। ग्रामीण इलाकों में भी हवा खराब हो सकती है, खासतौर पर जंगलों की आग से उठने वाला धुआं इसका बड़ा कारण बन रहा है। देखा जाए तो यह अध्ययन कनाडा में रहने वाले लोगों पर किया गया है, जहां कि वायु गुणवत्ता कई देशों से बेहतर मानी जाती है, फिर भी शोधकर्ताओं का कहना है कि पीएम2.5 का कोई सुरक्षित स्तर नहीं है। यही वजह है कि नीति निर्माताओं को ऐसे अध्ययनों से सीख लेकर प्रदूषण के जोखिम को और कम करने की जरूरत है। अध्ययन में इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय अक्सर उद्योगों या व्यस्त सड़कों के पास रहते हैं, जिसकी वजह से उनपर कहीं ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। वहीं, ल्यूपस जैसी ऑटोइम्यून बीमारियां महिलाओं और आदिवासी समुदाय को अधिक प्रभावित करती हैं।

हर सांस में खतरा-गौरतलब है कि इससे पहले भी यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना द्वारा किए एक अन्य अध्ययन में सामने आया था कि लम्बे समय तक वायु प्रदूषण के संपर्क में रहने से रूमेटाइड अर्थराइटिस यानी गठिया का जोखिम 40 फीसदी तक बढ़ सकता है। इसी तरह वायु प्रदूषण से क्रोहन रोग और अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी आंत सम्बन्धी बीमारियों का खतरा 20 फीसदी, और ल्यूपस जैसी ऊतकों को नुकसान पहुंचाने वाली बीमारियों का जोखिम 15 फीसदी तक बढ़ सकता है। 2024 में की एक अन्य रिसर्च से पता चला है कि लंबे समय तक दूषित हवा में सांस लेने से ल्यूपस नामक बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में इस अध्ययन का सन्देश स्पष्ट है, साफ हवा सिर्फ सांसों के लिए नहीं, बल्कि हमारे इम्यून सिस्टम और पूरे शरीर की सेहत के लिए भी बेहद जरूरी है। हमारे आसपास हवा में मौजूद प्रदूषण के अदृश्य कण चुपचाप हमारी रोग-प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर रहे हैं और भविष्य की गंभीर बीमारियों की जमीन तैयार कर रहे हैं। भारत में वायु गुणवत्ता से जुड़ी ताजा जानकारी आप डाउन टू अर्थ के एयर क्वालिटी ट्रैकर से प्राप्त कर सकते हैं।

जलवायु संकट: हिमालय और इंडो-बर्मा में औषधीय पौधे विलुप्ति की कगार पर

पूर्वी हिमालय और इंडो-बर्मा में जलवायु परिवर्तन से औषधीय पौधों, पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय जीवन पर पड़ते प्रभाव का अध्ययन

आज हमारा मौसम और पर्यावरण तेजी से बदल रहा है। इसे हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। यह सिर्फ मौसम पर असर नहीं डाल रहा, बल्कि हमारे जंगल, पौधे और जीव-जंतु भी बदल रहे हैं। भारत के पूर्वी हिमालय और भारत-बर्मा के जंगल बहुत खास हैं। यहां के पौधे और जानवर बहुत अलग औरअनोखे हैं। यही नहीं, यहां के स्थानीय लोग इन जंगलों के औषधीय पौधों पर अपने इलाज और दवाइयों के लिए भरोसा करते हैं, लेकिन अब यह भरोसा खतरे में है।

जलवायु परिवर्तन का औषधीय पौधों पर असर-शोधकर्ताओं ने इस क्षेत्र के औषधीय पौधों पर जलवायु परिवर्तन के असर का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि बढ़ता तापमान, कम या ज्यादा बारिश और बदलते मौसम ने इन पौधों के रहने की जगह को बदल दिया है। कुछ पौधे अब ऊंचे पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो बदलते मौसम के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहे और उनके खत्म होने का डर है।

स्थानीय लोगों पर असर-स्थानीय लोगों के लिए इसका मतलब बहुत बड़ा है। अगर औषधीय पौधे खत्म हो गए, तो उनके पास इलाज के लिए प्राकृतिक दवाइयां नहीं रहेंगी। इसके साथ ही पारंपरिक ज्ञान भी धीरे-धीरे खो जाएगा, क्योंकि नई पीढ़ियां इन पौधों और उनके उपयोग के बारे में सीखने का मौका नहीं पाएंगी। उदाहरण के तौर पर, कुछ खास जड़ें जैसे रहिजोम्स हैं जो पाचन और त्वचा के रोग में काम आती हैं। शोध में देखा गया कि अब ये जड़ें कम मिलने लगी हैं। अगर तापमान बढ़ता रहा, तो कई जगहें अब इन पौधों के लिए अनुकूल नहीं रहेंगी। इसका असर केवल स्वास्थ्य पर नहीं, बल्कि स्थानीय वैद्य और उनके परिवार की आमदनी पर भी पड़ेगा।

समाधान: स्थानीय सहभागिता और संरक्षण -शोध पत्र में शोधकर्ता के हवाले से कहा गया है कि इस समस्या का समाधान सिर्फ जंगलों को बचाने में नहीं है। स्थानीय लोगों को भी इसमें शामिल करना जरूरी है। अगर लोग पौधों की संख्या और मौसम के बदलाव पर नजर रखें, तो वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इन पौधों की रक्षा की जा सकती है। इससे न केवल पौधे बचेंगे, बल्कि पारंपरिक इलाज की कला भी बनी रहेगी।

आर्थिक और सामाजिक असर-जलवायु परिवर्तन का असर केवल स्वास्थ्य पर नहीं है। जब औषधीय पौधे कम हो जाते हैं, तो वैद्य अब इन्हें दूर-दूर से लाने पर मजबूर हो जाते हैं। इससे खर्च बढ़ता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। इसलिए यह केवल पर्यावरण की समस्या नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और आजीविका की भी चुनौती है।

वैश्विक नजरिया और सहयोग-वैश्विक स्तर पर भी इन जंगलों और पौधों की रक्षा के लिए कदम उठाना जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग से फंड और संसाधन मिल सकते हैं, जिनसे स्थानीय समुदायों को मदद मिलती है और औषधीय पौधों का संरक्षण आसान होता है। डिस्कवर प्लांट्स नामक पत्रिका में प्रकाशित शोध में कहा गया है कि औषधीय पौधों और उनके ज्ञान की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम स्थानीय ज्ञान और वैज्ञानिक तरीकों को मिलाकर काम करें, तो पौधों को बचाया जा सकता है और स्वास्थ्य और सांस्कृतिक धरोहर भी सुरक्षित रह सकती है। इस शोध का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हम प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ये अमूल्य संसाधन खो सकते हैं। वैज्ञानिक, नीति निर्माता और स्थानीय लोग मिलकर ही एक स्थायी और सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। इस तरह, हिमालय और भारत -बर्मा के औषधीय पौधों की सुरक्षा सिर्फ जंगलों की नहीं, हमारी संस्कृति, स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा है।

वैज्ञानिकों ने चेताया, सदी के अंत तक गायब हो सकते हैं अमेजन के 38 फीसदी जंगल

जलवायु परिवर्तन और भूमि उपयोग में आता बदलाव मिलकर दुनिया के सबसे बड़े वर्षावन को 'टिपिंग पॉइंट' की ओर धकेल रहे हैं, जहां से उसकी वापसी नामुमकिन हो सकती है। अमेजन सिर्फ जंगल नहीं, पृथ्वी के फेफड़े भी हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने चेताया है कि दुनिया के ये सबसे ब३०ड़े वर्षावन सदी के अंत तक अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी जंग लड़ सकते हैं।

जर्मनी की लुडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख से जुड़े शोधकर्ताओं के नेतृत्व में किए एक नए अध्ययन के मुताबिक, जलवायु परिवर्तन और भूमि उपयोग में बदलाव के चलते सदी के अंत तक अमेजन के 38 फीसदी जंगल खत्म हो सकते हैं। यह एक ऐसा नुकसान है जो पूरी पृथ्वी की जलवायु को हिला सकता है। करीब 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला अमेजन केवल पेड़ों का जंगल नहीं। यह जैव विविधता का वैश्विक केंद्र भी है, जो लाखों वनवासी समुदायों का घर है और पृथ्वी की जलवायु को संतुलित रखने की सबसे बड़ी प्राकृतिक ढालों में से एक है। वैज्ञानिकों के मुताबिक, अमेजन के पेड़ों और मिट्टी में धरती के कुल जमीनी कार्बन का करीब 10 फीसदी जमा है।

जंगल जो खुद को रखता है जिंदा:अमेजन की सबसे अनोखी खासियत उसकी 'खुद को जीवित रखने की क्षमता है। यह जंगल समुद्र से नमी खींचकर देश के अंदरूनी हिस्सों तक ले जाता है। यहां बारिश होती है, पानी वाष्प बनता है और फिर दोबारा बरसता है। इस प्राकृतिक चक्र के सहारे अमेजन हजारों वर्षों से फलता-फूलता आया है। लेकिन यह संतुलन अब टूटने की कगार पर है। कृषि और पशुपालन के लिए जिस तरह जंगलों को काटा जा रहा है, उसके साथ ही बढ़ता वैश्विक तापमान अमेजन को सूखे और भीषण गर्मी की ओर धकेल रहे हैं। भूमि उपयोग में बदलाव और जलवायु परिवर्तन ये दोनों पहले ही अमेजन को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं था कि ये दोनों मिलकर एक-दूसरे को कैसे प्रभावित कर रहे हैं और भविष्य में जंगलों का क्या हाल होगा।

'टिपिंग पॉइंट' का खतरा-वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी चिंता है जंगलों का अचानक से खत्म होना, जब घना जंगल धीरे-धीर नहीं बल्कि तेजी से सवाना जैसी खुली भूमि में बदल जाए। अगर ऐसा बड़े पैमाने पर हुआ, तो अमेजन एक ऐसे 'टिपिंग पॉइंट' पर पहुंच सकता है, जहां से उसकी वापसी असंभव हो जाएगी और यह पारिस्थितिकी तंत्र हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लुडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख की भूगोलविद सेल्मा बुल्टन के नेतृत्व में किए गए इस अध्ययन ने पहली बार भूमि उपयोग में आ रहे बदलावों और जलवायु परिवर्तन दोनों के संयुक्त प्रभाव का व्यवस्थित विश्लेषण किया गया है।

भविष्य की भयावह तस्वीर-अध्ययन में शोधकर्ताओं ने अर्थ सिस्टम मॉडलों की मदद से 1950 से 2014 तक अमेजन में काटे गए वनों का अध्ययन किया है और दो अलग-अलग जलवायु परिदृश्यों के आधार पर भविष्य का अनुमान लगाया है। इस अध्ययन के जो नतीजे सामने आए हैं वे दर्शाते हैं कि 1950 में मौजूद अमेजन के जंगल का 38 फीसदी हिस्सा सदी के अंत तक नष्ट हो सकता है। इसमें 25 फीसदी नुकसान भूमि उपयोग में आ रहे बदलाव से जबकि 13 फीसदी बढ़ते तापमान की वजह से होगा। देखा जाए तो यह आंकड़ा बेहद चिंताजनक है, क्योंकि पहले के अध्ययनों में चेतावनी दी जा चुकी है कि 20 से 25 फीसदी जंगल के खत्म होते ही अमेजन टिपिंग पॉइंट को पार कर सकता है। अध्ययन में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि अगर वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि 2.3 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाती है, तो जंगल के अचानक और बड़े पैमाने पर खत्म होने का खतरा तेजी से बढ़ जाएगा। वहीं यदि मौजूदा नीतियों और देशों द्वारा की गई घोषणाओं को देखें तो वैज्ञानिकों के मुताबिक दुनिया तापमान में कम से कम 2.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की ओर बढ़ रही है।

कश्मीर में जलवायु परिवर्तन के अनुकूल फसलों पर शोध, अरहर की नई किस्मों का परीक्षण

हिमालयी क्षेत्र कश्मीर में जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान (इक्रीसेट) और शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कश्मीर के बीच एक औपचारिक समझौता हुआ है। इसका उद्देश्य क्षेत्र की बदलती कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप जलवायु-सहिष्णु फसलों पर शोध को आगे बढ़ाना है। इस साझेदारी के तहत कश्मीर घाटी के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अरहर (तूर/पिजनपी) की नई किस्मों के परीक्षण किए जा रहे हैं। इन परीक्षणों का उद्देश्य जल्दी पकने वाली, प्रकाश-संवेदनशील, ताप-असंवेदनशील और ठंड सहन करने वाली किस्मों की अनुकूलता का आकलन करना है, वो भी ऐसे समशीतोष्ण और ठंड-प्रवण क्षेत्रों में जहां पारंपरिक रूप से अरहर की खेती नहीं होती रही है। इक्रीसेट के महानिदेशक हिमांशु पाठक ने कहा कि जैसे-जैसे हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन कृषि का स्वरूप बदल रहा है, राष्ट्रीय संस्थानों के साथ घनिष्ठ साझेदारी किसानों तक टिकाऊ फसल समाधान पहुंचाने के लिए बेहद जरूरी है। हाल ही में इक्रीसेट की एक शोध टीम ने शेर-ए-कश्मीर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर सगाम स्थित माउंटेन क्रॉप रिसर्च स्टेशन में प्रायोगिक स्थलों का दौरा किया और परीक्षण में शामिल किस्मों के प्रदर्शन की समीक्षा की। यह कार्य इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अरहर की खेती अब तक ठंड के प्रति संवेदनशीलता के कारण

मुख्यत: उष्णकटिबंधीय और उप-उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक सीमित रही है, लेकिन वर्तमान में चल रहे परीक्षण इस पारंपरिक सीमा को तोड़ते नजर आ रहे हैं। इस परीक्षण में साइटोप्लाज़्मिक मेल स्टेराइल लाइनों, मेंटेनर और रेस्टोरर लाइनों तथा उन्नत प्रजनन सामग्री का मूल्यांकन शामिल है। इक्रीसेट के उप महानिदेशक (अनुसंधान एवं नवाचार) डॉ. स्टैनफोर्ड ब्लेड ने कहा, इस वर्ष की शुरुआत में हमारी टीम ने कश्मीर का दौरा कर मुख्यमंत्री और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से क्षेत्र की कृषि आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने पर चर्चा की थी। उसके बाद जो प्रगति हुई है, वह सरकार और हमारे साझेदारों की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिससे घाटी के किसानों तक जलवायु-सहिष्णु नवाचार पहुंचाए जा सकें। इक्रीसेट में ग्लोबल सीड सिस्टम्स के प्रमुख डॉ. मंजूर डार ने कहा, प्रारंभिक अवलोकनों से कई आशाजनक प्रविष्टियों में पौधों की मजबूत वृद्धि, ठंडी रातों के तापमान को सहन करने की क्षमता और स्थिर पुष्पन व्यवहार सामने आया है। यदि ये परिणाम आगे के मौसमों में भी पुष्ट होते हैं, तो इससे न केवल कश्मीर घाटी में अरहर को भविष्य की एक व्यवहार्य फसल के रूप में स्थापित करने का मार्ग खुलेगा, बल्कि फसल विविधीकरण, खाद्य और पोषण सुरक्षा तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन भी बढ़ेगा। इसके साथ ही स्थानीय किसानों के लिए विशेष बाजारों में अवसर भी पैदा हो सकते हैं। गौरतलब है कि अरहर में सीएमएस तकनीक पर इक्रीसेट का शोध वर्ष 2008 से जारी है, जब दुनिया की पहली सीएमएस संकर अरहर किस्म (आईसीपीएच 2671) विकसित की गई थी। वर्तमान प्रगति राज्य में संकर बीज उत्पादन प्रणालियां स्थापित करने के नए अवसर खोल रही है। इसके फायदों में कीट प्रकोप में कमी, लंबी फूल अवधि और ऑफ-सीजन अरहर उत्पादन की संभावना शामिल है।

अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड से दिमागी संरचना पर असर 30,000 लोगों के ब्रेन स्कैन से खुलासा

30,000 लोगों के ब्रेन स्कैन से पता चला कि अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड दिमाग की संरचना बदलकर ज्यादा खाने की आदत को बढ़ावा दे सकते हैं

हाल ही में की गई एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक शोध में यह सामने आया है कि अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड का अधिक सेवन हमारे दिमाग की संरचना को प्रभावित कर सकता है। इस अध्ययन में लगभग 30,000 लोगों के ब्रेन स्कैन का विश्लेषण किया गया। शोधकर्ताओं ने पाया कि जो लोग नियमित रूप से अल्ट्रा-प्रोसेस्ड भोजन खाते हैं, उनके दिमाग में कुछ ऐसे बदलाव दिखाई देते हैं जो ज्यादा खाने की आदत को बढ़ावा दे सकते हैं।

अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड क्या होते हैं?-अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड वे खाद्य पदार्थ होते हैं जो फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं और जिनमें प्राकृतिक सामग्री के साथ-साथ कई तरह के केमिकल, एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स, रंग, स्वाद बढ़ाने वाले तत्व और इमल्सीफायर मिलाए जाते हैं। इनमें शामिल हैं-

पैकेट वाले चिप्स

प्रोसेस्ड मीट (सॉसेज, सलामी)
इंस्टेंट नूडल्स
मीठे ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स
पैकेट वाले केक और बिस्कुट
ये खाद्य पदार्थ स्वाद में अच्छे लगते हैं, सस्ते

होते हैं और आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन इनका अधिक सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है।

शोध में क्या पाया गया?

अध्ययन के अनुसार, अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाने वाले लोगों के दिमाग के उन हिस्सों में बदलाव देखे गए जो भूख, संतुष्टि और आत्म-नियंत्रण से जुड़े होते हैं। इसका मतलब यह है कि ऐसे लोग पेट भर जाने के बाद भी खाना जारी रख सकते हैं या उन्हें खाने पर नियंत्रण करना मुश्किल हो सकता है। शोध पत्र में शोधकर्ता के हवाले से कहा गया है कि यह अध्ययन यह साबित नहीं करता कि अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड सीधे दिमाग को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन दोनों के बीच एक मजबूत संबंध जरूर दिखता है। यह असर केवल मोटापे या शरीर में सूजन की वजह से नहीं है, बल्कि हो सकता है कि इन खाद्य पदार्थों में मौजूद केमिकल एडिटिव्स भी इसमें भूमिका निभाते हों।

सभी प्रोसेस्ड फूड खराब होते हैं?-नहीं, सभी प्रोसेस्ड फूड नुकसानदायक नहीं होते। कुछ प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ सेहत के लिए अच्छे और जरूरी भी होते हैं। उदाहरण के लिए-
जमी हुई सब्जियां (फ्रोजन वेजिटेबल्स)
दूध का पाश्चुरीकरण
दालें और अनाज जो साफ करके पैक किए जाते हैं
इनका उद्देश्य भोजन को सुरक्षित बनाना और पोषण बनाए रखना होता है। समस्या तब होती है जब भोजन बहुत ज्यादा केमिकल्स और कृत्रिम तत्वों से भरा हो।

अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड क्यों खतरनाक हो सकते हैं?

अधिक नमक, चीनी और खराब फैट से भरे होते हैं
जल्दी भूख लगने का कारण बनते हैं
खाने की लत को बढ़ा सकते हैं

जब ये दिमाग के नियंत्रण केंद्रों को प्रभावित करते हैं, तो व्यक्ति बार-बार खाने की इच्छा महसूस करता है, जिससे मोटापा, डायबिटीज और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

क्या है शोध के सुझाव?

यह शोध केवल व्यक्तिगत सेहत के लिए ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी अहम है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लोगों को अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड कम खाने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए। फूड इंडस्ट्री पर सख्त नियम बनाए जाने चाहिए। खाद्य उत्पादों में इस्तेमाल होने वाले एडिटिव्स की निगरानी जरूरी है। एनपीजे मेटाबोलिक हेल्थ एंड डिजीज में प्रकाशित इस अध्ययन से यह साफ होता है कि अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड सिर्फ शरीर ही नहीं, बल्कि दिमाग को भी प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि शोधकर्ताओं ने कहा है कि इस पर और शोध की जरूरत है, लेकिन अभी के सबूत यह बताते हैं कि ऐसे भोजन से दूरी बनाना हमारी सेहत के लिए बेहतर है। ताजा, प्राकृतिक और कम प्रोसेस्ड भोजन चुनना एक स्वस्थ जीवन की ओर महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

दिल्ली-एनसीआर में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, दोपहर बाद मौसम बदलने के आसार

नई दिल्ली, एजेंसी। देश के कई हिस्सों में चल रही भीषण गर्मी और लू के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बड़ी राहत भरी खबर दी है. मौसम विभाग ने आज 21 राज्यों में भारी बारिश, गरज-चमक के साथ आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. दिल्ली में कल गुरुवार को ज्यादातर इलाकों में दिन चढ़ने के साथ ही धूप भी तीखी और तेज हो गई. हालांकि, बीच-बीच में बादलों की आवाजाही होती रही. मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.6 डिग्री ज्यादा है. न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2.7 डिग्री कम है. आर्द्रता का स्तर 42 से 92 फीसदी तक रहा. मौसम विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार को अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री के बीच रहेगा. न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार 29, 30 जून और 1 जुलाई को दिल्ली-एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. दोपहर या शाम के समय आंधी-तूफान, बिजली कड़कने के साथ हल्की बारिश देखी जा सकती है. हवा की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. 29 और 30 जून को दिल्ली में अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सिसय रिकॉर्ड किया जा सकता है. केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 127 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 108, गुरुग्राम में 133, गाजियाबाद में 115, ग्रेटर नोएडा में 122 और नोएडा में 118 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में आईक्यू लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में आईक्यू लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर शब्बीर चौधरी को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यमुनापार और उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हत्या, रंगदारी और गैंगवार जैसी वारदातों को अंजाम देने वाले संगठित अपराध सिंडिकेट के सरगना गैंगस्टर शब्बीर अली उर्फ शबीर चौधरी को गिरफ्तार कर बड़ी

सफलता हासिल की है. शबीर अप्रैल 2025 से स्पेशल सेल के मामले में फरार चल रहा था. उसकी गिरफ्तारी हरियाणा के शंभू बॉर्डर से की गई. पुलिस के अनुसार, शबीर चौधरी-हाशिम बाबा-अनवर चाचा गैंग के संगठित अपराध का मुखिया है. यह गिरोह सीलमपुर, मौजपुर, भजनपुरा, शाहदरा समेत पूरे ट्रांस-यमुना क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय रहा है. गैंग के सदस्य हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी, जमीन कब्जाने और अन्य संगीन अपराधों में शामिल रहे हैं. पुलिस का दावा है कि इस सिंडिकेट के कुछ सदस्य नेपाल और दुबई से भी नेटवर्क संचालित कर रहे थे. स्पेशल सेल की टीम ने खुफिया सूचना और तकनीकी निगरानी के आधार पर शबीर को दबोचा. उसके कब्जे से एक कार और एक स्कूटी बरामद की गई है.मामले में गैंग के नौ अन्य सदस्य पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं. पुलिस के अनुसार, शबीर मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और 1990 के दशक से अपराध की दुनिया में सक्रिय है.

इलाज में बरती जा रही गंभीर लापरवाही की शिकायतों पर एक्शन की तैयारी है

फोर्टिस अस्पताल पर मरीज के इलाज में गंभीर लापरवाही के आरोप, सीएम रेखा गुप्ता के आदेश पर अब होगी कार्रवाई

नई दिल्ली, एजेंसी। शालीमार बाग स्थित फोर्टिस अस्पताल में अनियमिताएं और मरीजों के इलाज में बरती जा रही गंभीर लापरवाही की शिकायतों पर एक्शन की तैयारी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अस्पताल के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद गुरुवार को विभिन्न विभागों की टीम ने अस्पताल की जांच की और वहां कई अनियमितताएं पाई. शासन ने फोर्टिस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय लिया है. विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार की जा रही है. गौरतलब है कि हाल ही मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में सुनवाई के दौरान एक परिवार ने मुख्यमंत्री को शिकायत की थी कि शालीमार बाग क्षेत्र में उनके बेटे सुनील झा को चाकू मारकर घायल कर दिया गया था. उनके बेटे को फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया. पिता मिथलेश झा ने आरोप लगाया कि अस्पताल ने उसका इलाज करने से पहले उनसे धनराशि की मांग की. त्वरित व सही समय पर इलाज न मिल जाने पर उनके बेटे की मौत हो गई. इस घटना से आहत मुख्यमंत्री ने अस्पताल में बरती जा रही अनियमितताओं व मरीजों के इलाज में बरती जा रही गंभीर लापरवाही को देखते हुए जांच के आदेश जारी किए थे. गुरुवार को मध्य-उत्तरी जिला के डीएम एसएस परिहार के नेतृत्व ने स्वास्थ्य, नगर निगम, अग्निशमन व अन्य विभागों ने अस्पताल की जांच की. इस दौरान उन्हें कई शिकायतें मिलीं. बिल्डिंग बायलॉज का दुरुपयोग, अवैध निर्माण, आग बुझाने के सिस्टम में गड़बड़ी, बेसमेंट का मिसयूज और चिकित्सीय नियमों के लिए बनाई गई एसओपी में भी गंभीर लापरवाही भी पाई गई.

टीम ने सीसीटीवी फुटेज की जांच कर पाया कि जो युवक चाकू लगने से मारा गया था, वह खुद चलकर इमरजेंसी में पहुंचा था. इससे यह अहसास होता है कि अगर उसका सही समय पर इलाज होता तो उसकी जान बच जाती. टीम ने इमरजेंसी विभाग के रिकॉर्ड की भी जांच की है. डीएम के अनुसार इन अनियमितताओं व मरीजों के इलाज में बरती गई लापरवाही को ध्यान में रखते हुए अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय लिया गया है. जांच की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है.

अब हर महीने के दूसरे शनिवार और सभी रविवार को होगा ट्रैफिक चालानों का निपटारा

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली की सभी ज़िला अदालतों में समझौते योग्य सभी चालानों का निपटारा हर महीने के दूसरे शनिवार और सभी रविवार को वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट में किया जाएगा. यह वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट नाम से एक नई पहल शुरू की गई है. इसका समय सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक किया जाएगा. एक दिन में किसी एक गाड़ी के ज़्यादा से ज़्यादा 20 चालान डाउनलोड किए जा सकते हैं. उल्लंघनकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार चालान डाउनलोड करते समय कोर्ट कॉम्प्लेक्स, पेशी की तारीख और समय (सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक या दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक) चुन सकते हैं. उल्लंघनकर्ताओं को चयनित तिथि और समय पर संबंधित न्यायालय परिसर (उनके चयन के अनुसार) में जाना होगा और अपने चालय निपटारे के लिए संबंधित न्यायाधीश के समक्ष चालान पर्ची का प्रिंट आउट प्रस्तुत करना होगा. नई दिल्ली जिले की प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) अंजू बजाज चांदना द्वारा सभी जिला अदालतों इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है. लोक अदालत में एक गाड़ी के एक बार में सिर्फ पांच ही चालान डाउनलोड किए जा सकते थे. इससे ज्यादा चालान वाली गाड़ियों के चालानों का निपटारा कराने में लोगों को कई महीने लग जाते थे. लेकिन, अब वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट में एक गाड़ी के एक दिन में 20 चालान डाउनलोड करने तक की छूट देने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.

90 लाख की चोरी और ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने किया खुलासा

नई दिल्ली, एजेंसी। करोल बाग के बीडनपुरा स्थित एक मोबाइल थोक व्यापारी की दुकान में हुई 90 लाख रुपये की सनसनीखेज चोरी का दिल्ली पुलिस ने कुछ ही घंटों में पर्दाफाश कर दिया. मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर 84 लाख रुपये नकद, चोरी किए गए मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किया गया है. चौंकाने वाली बात यह है कि वारदात का मास्टरमाइंड दुकान का ही भरोसेमंद कर्मचारी निकला. जॉइंट पुलिस कमिश्नर मधुर वर्मा के अनुसार, 24 जून को दुकान मालिक ने शिकायत दी कि रात के दौरान उसकी दुकान से करीब 90 लाख रुपये नकद, पांच मोबाइल फोन और सीसीटीवी सिस्टम का डीवीआर चोरी हो गया है. सूचना मिलते ही करोल बाग थाना पुलिस, क्राइम टीम और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और कर्मचारियों से

पूछताछ के दौरान पुलिस को शक हुआ कि वारदात में किसी अंदरूनी व्यक्ति का हाथ है. जांच आगे बढ़ने पर दुकान के कर्मचारी रवि उर्फ महिपाल और उसके साथियों अंश, मनीष और दीपांशु की भूमिका सामने आई. पूछताछ में खुलासा हुआ कि रवि दुकान बंद करने और चाबियों की जिम्मेदारी संभालता था. उसे पता था कि दुकान में बड़ी मात्रा में नकदी रखी जाती है. उसने अपने साथियों के साथ मिलकर चाबी की डुप्लीकेट तैयार करवाई और चोरी की साजिश रची. 23-24 जून की रात आरोपी बिना ताला तोड़े डुप्लीकेट चाबी से दुकान में दाखिल हुए और नकदी, मोबाइल फोन तथा डीवीआर लेकर फरार हो गए. चोरी के बाद रवि खुद को निर्दोष दिखाने के लिए अगले दिन सामान्य कर्मचारी की तरह दुकान पहुंच गया. डीसीपी रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि करोल बाग थाना पुलिस और सेंट्रल जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने समन्वित कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में मामले का खुलासा कर दिया. आरोपियों से पूछताछ के आधार पर शेष रकम और अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है. वही, दूसरे केस में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. पुलिस और स्पेशल स्टाफ ने एक सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर केस का पर्दाफाश करते हुए तीन नाबालिग आरोपियों को पकड़ लिया है. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल दो चाकू और आरोपियों के कपड़े भी बरामद किए हैं. डीसीपी रोहिणी शशांक जायसवाल के अनुसार 23 जून 2026 को बेगमपुर थाना क्षेत्र के पंसाली रोड पर एक व्यक्ति के घायल अवस्था में पड़े होने की सूचना मिली थी.

दिल्ली के बवाना में युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग, संगम विहार में पत्नी की गोली मारकर हत्या, पति फरार

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के बवाना थाना इलाके के पुठ खुर्द गांव में दिनदहाड़े एक युवक की गोलियों से भूनकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. वारदात को अंजाम देने के लिए पहले से घात लगाए बैठे हथियारबंद हमलावरों ने युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. जानकारी के मुताबिक मृतक युवक की पहचान 22 वर्षीय केशव के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि केशव पर करीब 4 से 5 हमलावरों ने अचानक हमला किया. हमलावरों ने उस पर कई राउंड गोलियां चलाईं. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मौके पर करीब 8 से 10 राउंड फायरिंग की आवाज सुनाई दी. इस गोलीबारी में केशव को करीब 5 से 6 गोलियां लगीं, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर गया. घटना के तुरंत बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात की सूचना मिलते ही बवाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके. प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका है कि हत्या के पीछे आपसी रंजिश हो सकती है. बताया जा रहा है कि मृतक के परिवार में पहले भी कई हत्याएं हो चुकी हैं, जिसके चलते पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है।

डीआरडीओ की स्मार्ट बाइक एंबुलेंस 'रक्षिता' तैयार, अब तंग गलियों में भी मरीजों को मिलेगी मेडिकल हेल्प

नई दिल्ली, एजेंसी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 'रक्षिता' नाम की एक विशेष बाइक एंबुलेंस विकसित की है. इसकी खास बात यह है कि जिन इलाकों में एंबुलेंस की सुविधा नहीं पहुंच सकती वहां से गंभीर मरीजों को निकालने में यह सक्षम है. दूसरे शब्दों में संकरी गलियों और आपदा क्षेत्रों में यह काफी उपयोगी साबित होगी. यह बाइक ऑक्सीजन सपोर्ट, ईसीजी मॉनिटरिंग और अन्य हेल्थ पैरामीटर से लैस है, साथ ही यह एंबुलेंस कम लागत में तेज और सुरक्षित मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने का दावा करती है. इस बाइक एंबुलेंस को भारत मंडपम में आयोजित इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो में प्रदर्शित किया गया. अभी तक जिन एंबुलेंस का इस्तेमाल हो रहा था वह चार पहिया एम्बुलेंस संकरे रास्ते और पतली गलियों में नहीं जा पाती थी. इस समस्या को देखते हुए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने एक बाइक एंबुलेंस को डिजाइन किया है. इस बाइक एंबुलेंस को इस तरीके से तैयार किया गया है कि उस पर मरीज को आसानी से बिठाकर सुरक्षित तरीके से अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाया सकता है. इस एंबुलेंस को रक्षिता नाम दिया गया है. यह बाइक एम्बुलेंस मरीज की देखभाल के लिए जितने पैरामीटर की जरूरत होती है, उन सभी पैरामीटर से लैस है. ऑक्सीजन लेवल, ईसीजी अपडेट सहित सारे हेल्थ पैरामीटर को इसमें लगाई गई स्क्रीन पर आसानी से देख सकते हैं. साथ ही बाइक एंबुलेंस की चेयर के नीचे एक छोटा सा ऑक्सीजन का सिलेंडर भी रहता है.

वेनेजुएला में भूकंप के बाद तबाही का मंजर; मलबे में अपनों को ढूंढ रहे लोग; हजारों लापता

काराकास , एजेंसी। वेनेजुएला में गुरुवार तड़के आए 2-2 ताकतवर भूकंप के बाद तबाही का मंजर पसरा हुआ है। हजारों लोग लापता है जिनकी खोज जारी है। घायल और परेशान लोग मलबे के ढेरों में अपनों की तलाश कर रहे हैं। वहीं सैकड़ों लोगों ने पार्क, पार्किंग और दूसरी खुली जगहों पर रात बिताई। दूसरी तरफ अब तक 188 मौतों की पुष्टि हो चुकी है और यह आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। राहत दल बचाव कार्य में जुटे हुए हैं।

अधिकारियों के मुताबिक बुधवार शाम आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो भूकंप से कई प्रांतों में भारी नुकसान हुआ है और कई इमारतें ढह गईं। ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से हैं। अधिकारियों के मुताबिक भूकंप के बाद देशभर में हजारों लोग लापता हैं। उन्होंने बताया कि राजधानी काराकस के उत्तर में स्थित ला गुएरा के तटीय इलाके में जानमाल का सबसे ज्यादा नुकसान दर्ज किया गया है।

अपनों की तलाश में बिलख रहे लोग

उत्तरी वेनेजुएला के शहरों में इस वक्त चीख-पुकार और मातम का माहौल है। मलबे से धूल और खून से सने लोगों, बच्चों और बेजुबान जानवरों को निकाला जा रहा है। वेनेजुएला के

सरकारी टीवी पर दिखाए गए वीडियो में एक जगह सीमेंट के भारी-भरकम स्लैब के नीचे एक महिला दबी हुई थी, जिसका सिर्फ एक नंगा पैर बाहर दिखाई दे रहा था। रेस्क्यू टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे जिंदा बाहर निकाला।

मलबे के पास खड़ी डायना डेलगाडो ने रोते हुए प्रशासन पर गुस्सा निकाला, 'सरकार ने जिस भारी मशीनरी का वादा किया था, वो कहां है? हमारे पड़ोसी खुद हाथों से मलबा खोद रहे हैं। मेरा 8 साल का बेटा लापता है, मुझे नहीं पता वो मलबे में है या किसी शेल्टर होम में।' एक अन्य जगह पर एक मां अपने 3 और 10 साल के बच्चों के शवों को कंबल में लिपटे देख रो पड़ी।

अब तक 235 की मौत: इस बीच वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने गुरुवार को कहा है कि भूकंप में कम से कम 235 लोगों की मौत हो गई और 4300 से अधिक लोग घायल हो गए। इससे फलद रॉड्रिगेज ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए आपातकाल की घोषणा की थी। अधिकारियों ने बताया कि स्कूलों को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है और कुछ स्कूल भवनों का इस्तेमाल राहत शिविरों और सहायता केंद्रों के तौर पर किया जाएगा।

'ला गुएरा' बना डिजास्टर जोन

राजधानी काराकास के उत्तर में स्थित तटीय क्षेत्र ला गुएरा इस आपदा का सबसे बड़ा शिकार बना है। एक रिटायर्ड शिक्षक जुआन अल्बर्टो ने बताया कि वे मलबे के बीच से गुजर रहे थे, जहां हर तरफ लाशें थीं। तभी उन्हें एक दबी हुई महिला दिखी जो हाथ हिलाकर मदद मांग रही थी, लेकिन संसाधन न होने के कारण वे बेबस थे। सोशल मीडिया पर सामने आए कुछ वीडियो में ला गुएरा में एक अस्पताल के बाहर दर्जनों लोगों का इलाज होते हुए देखा जा सकता है, इनमें से कुछ जमीन पर लेटे थे और कुछ बिस्तरों पर थे। देश का मुख्य अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ला गुएरा में ही है, जो भूकंप के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर बंद हो गया है।

शांति बहाल करने समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे

ईरान और अमेरिका के बीच अगले सप्ताह बातचीत फिर शुरू होने की उम्मीद, पाकिस्तान बना गारंटर

वाशिंगटन , एजेंसी। पाकिस्तान ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत अगले सप्ताह फिर से शुरू होने की उम्मीद है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने बुधवार देर रात जारी एक बयान में कहा कि सभी पक्ष बातचीत के लिए तैयार हैं और प्रक्रिया जारी है। अमेरिका और ईरान ने पिछले सप्ताह पश्चिम एशिया में शांति बहाल करने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे।

दोनों देशों ने स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में बातचीत की थी। पाकिस्तान ने इस समझौता ज्ञापन पर 'गारंटर' के रूप में हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद दोनों पक्ष 60 दिनों में अंतिम शांति समझौते की दिशा में एक रूपरेखा पर सहमत हुए। अंद्राबी के हवाले से जारी बयान में बताया गया कि बातचीत जारी है। मेरा मानना है कि बातचीत अगले सप्ताह, संभवतः मंगलवार को फिर से शुरू होगी। उन्होंने कहा, 22 जून की बातचीत के लिए हमारा प्रतिनिधिमंडल बर्गेनस्टॉक में मौजूद था। जहां तक मैं जानता हूं, जब अगले

सप्ताह बातचीत फिर से शुरू होगी, तब भी हमारा प्रतिनिधिमंडल वहां मौजूद रहेगा। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि अगले सप्ताह अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत दोबारा शुरू होने की संभावना एक सकारात्मक घटनाक्रम है। अमेरिका और ईरान ने हालांकि अब तक बातचीत दोबारा शुरू होने की संभावना को लेकर कोई बयान नहीं दिया है।

पश्चिम एशिया में तनाव में एक के बाद एक आ रहे अड़ंगों के बीच और एक स्थायी समाधान खोजने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में हाई-लेवल डिप्लोमेसी शुरू हो गई है। अमेरिकी मीडिया संस्थान 'एक्सियोस' (ॅ×द्वश्ह्य) की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों देशों के बीच पिछले हफ्ते हस्ताक्षरित 14-सूत्रीय समझौता ज्ञापन (रूश्) के तहत पहले दौर की तकनीकी बातचीत संपन्न हो गई है। इस दौरान लेबनान में सीजफायर बनाए रखने, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' को खुला रखने और संभावित परमाणु समझौते के प्रमुख पहलुओं पर गहन चर्चा हुई।

बांग्लादेशी राष्ट्रपति से मिले हाई कमिश्नर, 'टेबल ऑफ प्रिसिडेंस ' में मिला कैबिनेट मंत्री का दर्जा

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश में भारत के नए हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने गुरुवार को ढाका स्थित बंगभवन में राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपना परिचय पत्र सौंपकर औपचारिक रूप से अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। इस मौके पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया और प्रेसिडेंट गार्ड रेजिमेंट की एक चुस्त-दुरुस्त टुकड़ी ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। परिचय पत्र सौंपने के बाद दिनेश त्रिवेदी ने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन से शिष्टाचार मुलाकात की। बैठक में दोनों देशों के रिश्तों, सीमा से जुड़े मुद्दों और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे अहम विषयों पर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद राष्ट्रपति के प्रेस सचिव मो. सरवर आलम ने बताया कि राष्ट्रपति ने नए भारतीय हाई कमिश्नर का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि उनका कार्यकाल भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को और मजबूत करेगा तथा दोनों देशों के लोगों के लिए बेहतर परिणाम लेकर आएगा। राष्ट्रपति ने इस साल फरवरी में हुए आम चुनावों के बाद बनी नई लोकतांत्रिक सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा स्पीकर ओम

बिरला की मौजूदगी को भी याद किया और उसके लिए भारत के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश का करीबी पड़ोसी, महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार और विकास सहयोगी है। बांग्लादेश भारत के साथ सम्मानजनक, संतुलित और भविष्य को ध्यान में रखकर साझेदारी आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस पर दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि दोनों संप्रभु देशों के बीच स्वाभाविक रूप से मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं और भारत इन्हें और मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

कराची में 3 साल की मासूम बच्ची की रेप के बाद निर्मम हत्या, 12 संदिग्धों की जांच

कराची , एजेंसी। कराची में 3 साल की मासूम बच्ची की हत्या का यह दर्दनाक मामला पूरे देश में हलचल मचा रहा है। कराची में एक 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी और हत्या की गई है। दोपहर में घर से बाहर खेलने गई यह मासूम बच्ची उसी शाम एक बोरे में मृत पाई गई। इस खौफनाक घटना के बाद से पूरे इलाके में बहुत ज्यादा शोक और गहरा गुस्सा फैला हुआ है। बच्ची का शव कराची के मुस्लिमबाद में मुस्तफा मस्जिद के पास उसी की गली में मिला। शव को एक बोरे में बंद करके मासूम बच्ची के घर की गली के मेन गेट पर फेंका गया था। पाकिस्तानी अखबार डॉन के अनुसार डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में हिंसक बलात्कार की पुष्टि भी कर दी है। इस भयानक मामले ने सुरक्षा व्यवस्था और समाज की मानसिकता पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस दिल दहला देने वाले मामले में सबसे शर्मनाक बात यह है कि आरोपी कोई करीबी हो सकता है। पुलिस को गहरा शक है कि इस मासूम बच्ची का गुनाहगार उसका अपना ही कोई करीबी रिश्तेदार है। केस हैंडल करने वाले डॉ. सैयद ने इसे अपने मेडिकल करियर का सबसे डरावना मामला बताया है। उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ ऐसे अपराध हमेशा ही बेहद डरावने और बहुत परेशान करने वाले होते हैं। सिंध के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जावेद आलम ओधो ने इस घटना की तुरंत जांच के कड़े आदेश दिए हैं। उन्होंने इस जघन्य अपराध की गहराई से जांच के लिए एक बहुत ही हाई-लेवल टीम का गठन किया है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक संपादकः नीरज मेहरा द्वारा बोनस ग्राफिक्स, लक्ष्मी नगर, झोटवाड़ा मार्ग, अजमेर रोड, जयपुर-302006 से मुद्रित एवं 141, दयानन्द नगर, फेज प्रथम झालाना डूंगरी गली नंबर 19, थाना गांधी नगर, जयपुर (राज.) से प्रकाशित। प्रबंध संपादक- पी.के.बृजवाल, 9950325930, 9571635930 (कानूनी सलाहकार एडवोकेट कैलाशनाथ भट्ट)